

भ्रसाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I-- खण्ड 1

PART I-Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित



No 234

नई बिल्ली, बृहस्पतिबार, ग्रन्तूबर 19, 1972/म्राध्यिन 27, 1894 NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 19, 1972/ASVINA 27, 1894

इस भाग में भिन्न पुष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह ग्रसग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

# MINISTRY OF LABOUR AND REHABILITATION (Department of Labour and Employment)

#### RESOLUTION

New Delhi, the 19th October 1972

No. S-33025/23/72-WB.—The Government of India by their Resolution No. U-23018/1/72-WB, dated the 28th April, 1972, constituted the Bonus Review Committee to review the operation of the Payment of Bonus Act, 1965. The composition of the Committee is as follows:—

Chairman

Dr. B. K. Madan.

#### Members

- 1. Shri N. S. Bhat.
- 2. Shri Harish Mahindra.
- 3. Shri R. P. Billimoria.
- 4. Shri G. Ramanujam.
- 5. Shri Satish Loomba.
- 6. Shri Mahesh Desai.
- 7. Dr S. D. Punekar.

2. The Committee have submitted their interim findings on the terms of reference relating to the raising of the minimum bonus payable under the Act. The findings are contained in two separate reports one signed by the Chairman. Dr. S. D. Punekar, Shri N. S. Bhat and Shri Harish Mahendra, and the other by Shri R. P. Billimoria, Shri Mahesh Desai, Shri G. Ramanujam and Shri Satish Loomba.

\_\_\_\_\_

- 3. After careful consideration of the two reports Government have taken the following action:—
  - (a) An Ordinance has been promulgated on 23rd September, 1972 to provide that:
    - (i) the statutory minimum of the bonus payable to workers covered by the Payment of Bonus Act is raised from 4 per cent to 8-1/3 per cent for the accounting year commencing on any day in the year 1971; and
    - (ii) payment be made in full in cash to all persons covered by the Payment of Bonus Act upto 8-1/3 per cent. Where payments more than 8-1/3 per cent are to be made during the said accounting year the positive i.e. plus difference, if any, between the payments to be made during the said accounting year and the payments made during the accounting year 1970-71 (where they were in excess of 8-1/3 per cent will be deposited into the provident fund account of the beneficiaries.
  - (b) Executive instructions have been issued to the effect that pending formal amendment of the Act, public sector establishment which are at present not required to pay bonus by virtue of the provisions in Section 20 of the Payment of Bonus Act should also make payments on the above basis in respect of the accounting year commencing on any day in the year 1971; and
  - (c) Government have requested the Central Organisations of Employers to consider advising their constituents not to insist on recoveries of advances made to the employees in terms of the formula popularly known as the Khadilkar Formula.
- 4. Copies of the Reports submitted by the Bonus Review Committee are being printed and will be made available for sale through the Manager of Publications in the usual manner.

#### ORDER

Ordered that a copy of the Resolution be communicated to:-

- (i) All State Governments and Union Territories.
- (ii) All Ministries of the Government of India and Planning Commission.
- (iii) All India Organisations of Employers and Workers.

Ordered also that the Resolution be published in the Gazetted of India Extraordinary for general information.

N. P. DUBE, Addl. Secy.

## श्रम ग्रीर पुनर्वास मंत्रालय (श्रम ग्रीर रोजगार विभाग)

संकल्प

नर्ड दिल्ली, 19 प्रक्तूबर, 1972

सं० ए० 33025/23/72-डः ह्यू० बी०.—भारत सरकार ने भ्रपने संकल्प संख्या यू— 23018/1/72—डब्ल्यू० बी०, तारीख 28 अप्रैल, 1972 द्वारा बोनस भगतान अधिनियम, 1965 ने कार्यान्ध्यन का पुनरीक्षण करने के लिए बोनस पुनरीक्षा समिति। गठित की । समिति का गठन निम्न प्रकार है:—

डा० बी० के० मदान ग्रह्मध्वक्ष

- श्री एन० एस० भट्ट सदस्य
- 2. श्री हरिश महिन्दा

-----

- 3. श्री ग्रार० पी० बिल्लीमोरिया
- 4. श्री जी० रामानुजम
- 5. श्रीमशीशे लूम्बा
- 6. श्री महेश देसाई
- 7. डा• एस० डी० पुनेकर,
- 2. समिति ने श्रधिनियम के श्रस्तर्गत देय न्यूनतम बोनस को बढ़ाने से सम्बन्धित विचाराथ विवार पर अपने अन्तरिम निष्कष प्रस्तुत कर दिए हैं। निष्कर्ष दो पृथक्-पृथक् रिपोर्टी में दिए गए हैं—एक पर अध्यक्ष, डा॰ एस॰ डी॰ पुनेकर, श्री एन॰ एस॰ भट्ट और श्री हरीश महिन्द्र। ने और दूसरे पर श्री ग्रार॰ पी॰ बिल्लीमीरिया, श्री महेण देसाई, श्री जी॰ रामानुजम और श्री सतीश लुम्बा ने हस्तक्षर किए है।
- 3. उन्त दो रिपोर्टी पर ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद सरकार ने निम्नलिखित रार्यवाही की है:---
  - (क) 23 सिनम्बर, 1972 को एक ग्रध्यादेश जारी करके निम्नलिखित व्यवस्था की गई है।
    - (1) बोनस भूगतान अधिनियम, के अन्तर्गत आने वाले श्रमिकों को देय साविधिक न्यूनतम बोनस को 1971 वर्ष के किसी भी दिन से शुरु होने वाले लेखा वर्ष के लिए 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 8 र्रु प्रतिशत किया गया है ; और
    - (2) बोतम भुगतान ग्रिधिनियम के ग्रन्तर्गत ग्राने वाले सभी व्यक्तियों को 8 में प्रतिणत तक पूर्ण भुगतान नकद किया जाए । जहां उकत लेखा वर्ष के दौरान 8 में प्रतिणत में ग्रिधिक भुगतान किए जाने हैं, वहां उक्त लेखा वर्ष के दौरान किए जाने वाले भुगतानों ग्रौर लेखा वर्ष 1970-71 के दौरान किए गए भुगतानों के बीच का ग्रन्तर, यदि कोई हो (जहां वे 8 में प्रतिणत में ग्रिधिक थे) (वाह्य ग्रर्थात् ग्रितिण्वत राणि) लाभ पाने वालों के भविष्य निधि खातों में जमा कर दी जाएगी ।
  - (ख) इस आह्य के प्रधानिक आदेण जारों कर दिए गए हैं कि अधिनियम में औपचारिक संगोधन किए जाने तक, सरकारी क्षेत्र के ऐसे प्रतिष्ठानों को भी जिनको इस समय बोनस भुगतान अधिनियम की धारा 20 के उपबन्धों के अनुसार बोनस देना अपेक्षित नहीं है. वर्ष 1971 के किसी भी दिन को शुरू होने वाले लेखा वर्ष के सम्बन्ध में उक्त प्राधार पर भुगतान करना चाहिए। और

- (ग) मरकार ने नियोजकों के केन्द्रीय सगठनों से अन्दोध किया है कि वे अपने घटकों को सलाह देने पर विचार करें कि वे "खाडिल कर फार्मुला" के नाम से विख्याल फार्मुले के अनुपार कर्मचारियों को दो गई अग्रिम राशियों की बसूली पर जोर न दें।
- 4 बोनस पुनरीक्षा समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोटों की प्रतिया मृद्रित की जा रहीं है झौर उन्हें सामान्य रीति के धनुसार प्रकाशन प्रबन्ध के माध्यम से बिकी के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।

### ग्रावेज

ब्रदश दिया जाता है कि इस सकल्प की एक-एक प्रति निग्निकिखित की भेजी जाए -

- (i) सभी राज्य सरकारें श्रीर सम प्रशासित क्षेत्र ।
- (ii) भारत सरकार क सभी मत्रालय तथा योजना श्रायोग ।
- (iii) मानिको तथा मजदूरो के अखिल भारतीय सगठन ।

यह भी ब्रादेश दिया जाता है कि इस सक प को श्राम सुचना के लिए भारत के श्रसाधारण राजपत्र में प्रकाशित कराया जाए ।

नि० प्र० हुत्रे, ग्रपर मचित्र ।